

2015 का विधेयक सं.4

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवे वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता हैः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह 8 दिसम्बर, 2014 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 1994 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 19 का संशोधन.- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 19 में,-

(i) विद्यमान खण्ड (त) के पश्चात् और विद्यमान परन्तुक के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(थ) घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय रखता हो और उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए नहीं जाता हो;" ;

(ii) विद्यमान स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण-I के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जायेगा; और

(iii) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित स्पष्टीकरण-I के पश्चात् निम्नलिखित नया स्पष्टीकरण जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण-II.- इस धारा के खण्ड (थ) के प्रयोजन के लिए-

(i) "स्वच्छ शौचालय" से तीन दीवारों, एक दरवाजे और छत से घिरी हुई कोई जल-बंध (वाटर सील्ड) शौचालय प्रणाली या व्यवस्था अभिप्रेत है; और

(ii) "परिवार के सदस्य" से ऐसे व्यक्ति का/की पति/पत्नी, बच्चे और ऐसे व्यक्ति के साथ निवास कर रहे उसके माता-पिता अभिप्रेत हैं।"

3. निरसन और व्यावृत्तियां- (1) राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश सं. 1) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

सरकार ने यह विनिश्चय किया था कि पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के घरों में शौचालयों के सन्निर्माण और उनके नियमित उपयोग को अनिवार्य बनाया जाये।

उक्त प्रयोजन के लिए यह महसूस किया गया था कि कोई व्यक्ति, जो पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने का इच्छुक हो, उसका अपने घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय अवश्य हो और उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए नहीं जाता हो।

इसलिए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के उपबंधों को संशोधित किया जाना प्रस्तावित था।

चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 8 दिसम्बर, 2014 को राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश सं. 1) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4(ख) में दिनांक 8 दिसम्बर, 2014 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईम्प्रिट है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

सुरेन्द्र गोयल,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम
सं. 13) से लिये गये उद्धरण

XX

XX

XX

XX

XX

19. किसी पंच या सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अहताएं.- किसी पंचायती राज संस्था के मतदाताओं की सूची में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति ऐसी पंचायती राज संस्था के पंच या, यथास्थिति, सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हित होगा यदि ऐसा व्यक्ति-

(क) राजस्थान राज्य के विधानमण्डल के निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि द्वारा या उसके अधीन निरहित नहीं है:

परन्तु कोई भी व्यक्ति यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तो इस आधार पर निरहित नहीं होगा कि वह 25 वर्ष की आयु से कम का है;

(क क) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन और अनुसार फाइल की गयी किसी निर्वाचन याचिका के परिणामस्वरूप किसी सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा अष्ट आचरण का दोषी नहीं पाया गया है;

(ख) किसी स्थानीय प्राधिकरण, किसी विश्वविद्यालय या किसी भी ऐसे निगम, निकाय, उपक्रम या सहकारी सोसाइटी, जो राज्य सरकार द्वारा या तो नियंत्रित या पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित है, के अधीन कोई वैतनिक पूर्णकालिक या अंशकालिक नियुक्ति धारण नहीं करता है;

(ग) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अवचार के कारण राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत नहीं किया गया है और लोक सेवा में नियोजन के लिए निरहित घोषित नहीं किया गया है;

(घ) किसी भी पंचायती राज संस्था के अधीन कोई भी वैतनिक पद या लाभ का पद धारण नहीं करता है;

(ङ) संबंधित पंचायती राज संस्था से, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी भी संविदा में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अपने द्वारा या अपने भागीदार, नियोजक या कर्मचारियों के द्वारा कोई भी अंश या हित, किये गये किसी भी कार्य में ऐसे अंश या हित का स्वामित्व रखते हुए, नहीं रखता है;

(च) कुष्ठी नहीं है या कार्य के लिए असमर्थ बनाने वाले किसी भी अन्य शारीरिक या मानसिक दोष या रोग से ग्रस्त नहीं हैं;

(छ) किसी भी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है और छह मास या अधिक के कारावास से दण्डादिष्ट नहीं किया गया है, ऐसा दण्डादेश तत्पश्चात् उलट दिया गया हो या उसका परिहार कर दिया गया हो या अपराधी को क्षमा कर दिया गया हो;

(छ छ) ऐसे किसी सक्षम न्यायालय में विचारणाधीन नहीं हैं जिसने उसके विरुद्ध ऐसे किसी अपराध का, जो पांच वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय हो, संजान ले लिया है और आरोप विरचित कर दिये हैं;

(ज) धारा 38 के अधीन निर्वाचन के लिए तत्समय अपात्र नहीं हैं;

(झ) संबंधित पंचायती राज संस्था द्वारा अधिरोपित किसी भी कर या फीस की रकम, को, उसके लिए मांग नोटिस प्रस्तुत किये जाने की तारीख से दो मास तक असंदत्त नहीं रखे हैं;

(झ) संबंधित पंचायती राज संस्था की ओर से या उसके विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में नियोजित नहीं हैं;

(ट) राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम, 1960 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है;

(ठ) दो से अधिक बच्चों वाला नहीं है;

(ड) पूर्व में किसी पंचायती राज संस्था का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष रहते हुए पंचायती राज संस्था के शोध्यों को जमा कराने के लिए ऐसी तारीख से जबकि ऐसा नोटिस अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष पर तामील किया गया था, दो मास की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् भी शोध्य असंदत नहीं रखे हैं और उसका नाम, ऐसी पंचायती राज संस्था के निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी होने से कम से कम दो मास पूर्व, राज्य सरकार द्वारा कलक्टर (पंचायत) को उपलब्ध करायी गयी ऐसे व्यतिक्रमियों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है;

(ढ) राज्य में की अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किसी स्थान की दशा में, उन जातियों या जनजातियों या, यथास्थिति, वर्गों में से किसी का सदस्य है;

(ण) महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, महिला है; और

(त) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किसी स्थान की दशा में, उन जातियों या जनजातियों या, यथास्थिति, वर्गों में से किसी का सदस्य है और महिला है;

परन्तु-

(i) किसी व्यक्ति को किसी निगमित कम्पनी या राजस्थान राज्य में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सहकारी सोसाइटी में केवल अंशधारी या उसका सदस्य होने के कारण से कम्पनी या सहकारी सोसाइटी और पंचायती राज संस्था के बीच की गयी किसी भी संविदा में हितबद्ध नहीं ठहराया जायेगा;

(अ) खण्ड (क क) के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति खण्ड (क क) में निर्दिष्ट आदेश की तारीख से छह वर्ष की कालावधि के लिए निरहित समझा जायेगा;

- (ii) खण्ड (ग), (छ) और (ठ) के प्रयोजनों के लिए कोई भी व्यक्ति उसकी पदच्युति की तारीख या, यथास्थिति, दोषसिद्धि की तारीख से छह वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् निर्वाचन के लिए पात्र हो जायेगा;
- (iii) खण्ड (झ) के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को तब निरहित नहीं समझा जायेगा यदि वह उससे शोध्य कर या फीस की रकम अपना नामनिर्देशन दाखिल करने की तारीख के पूर्व संदत्त कर देता है;
- (iv) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख, जिसे इस परन्तुक में आगे ऐसे प्रारम्भ की तारीख कहा गया है, से 27 नवम्बर, 1995 तक की कालावधि के दौरान हुए किसी अतिरिक्त संतान के जन्म पर खण्ड (ठ) में उल्लिखित निरहता के प्रयोजन के लिए विचार नहीं किया जायेगा और कोई व्यक्ति जिसके दो से अधिक संतानें हैं (ऐसे प्रारम्भ की तारीख से 27 नवम्बर 1995 तक की कालावधि के दौरान जन्मी संतान, यदि कोई हो को छोड़कर) उस खण्ड के अधीन तब तक निरहित नहीं होगा जब तक ऐसे प्रारम्भ की तारीख को रही उसकी संतानों की संख्या में वृद्धि नहीं होती;
- (v) खण्ड (छ) के प्रयोजनों के लिए, किसी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को निरहित नहीं समझा जायेगा यदि वह अपना नामनिर्देशन पत्र फाइल करने के पूर्व उससे शोध्य रकम संदत्त कर देता है।

स्पष्टीकरण- धारा 19 के खण्ड (ठ) के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को या तत्पश्चात् जहां किसी दम्पती के पूर्ववर्ती प्रसव या प्रसर्वों से केवल एक बच्चा हो वहां किसी एक ही पश्चात्वर्ती प्रसव से पैदा हुए बच्चों की किसी संख्या को एक इकाई समझा जायेगा।

**THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT)
BILL, 2015**

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 8th December, 2014.

2. Amendment of section 19, Rajasthan Act No. 13 of 1994.- In section 19 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), hereinafter referred to as the principal Act,-

(i) after the existing clause (p) and before the existing proviso, the following new clause shall be inserted, namely:-

“(q) does not have a functional sanitary toilet in the house and any of his family members defecate in the open:”;

(ii) the existing Explanation shall be renumbered as **Explanation-I**; and

(iii) after the Explanation-I so renumbered, the following new Explanation shall be added, namely:-

“Explanation-II.- For the purpose of the clause (q) of this section-

(i) “sanitary toilet” means a water sealed toilet system or setup surrounded by three walls, a door and a roof; and

(ii) “family members” means spouse of such person, children and his parents living with such person.”.

3. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Ordinance, 2014 (Ordinance No. 1 of 2014) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Government had decided that construction and regular use of toilets in the houses of representatives of Panchayati Raj Institutions should be made compulsory.

For the purpose it had been felt that any person willing to contest elections for Panchayati Raj Institutions must have a functional sanitary toilet in his/her house and any of his/her family members do not defecate in the open.

Therefore, the provisions of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 were proposed to be amended.

Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, he, therefore, promulgated the Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Ordinance, 2014 (Ordinance No. 1 of 2014) on 8th December, 2014, which was published in Rajasthjan Gazette, Part IV(B), Extraordinary, dated 8th December, 2014.

The Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

सुरेन्द्र गोयल,
Minister Incharge.

**EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN
PANCHAYATI RAJ ACT, 1994
(Act No. 13 of 1994)**

XX XX XX XX

19. Qualifications for election as a Panch or a member.-

Every person registered as a voter in the list of voters of a Panchayati Raj Institution shall be qualified for election as a Panch or, as the case may be, a member of such Panchayati Raj Institution unless such person-

- (a) is disqualified by or under any law for the time being in force for the purposes of election to the Legislature of the State of Rajasthan :

Provided that no person shall be disqualified on the ground that he is less than 25 years of age if he has attained the age of 21 years;

- (aa) is found guilty of a corrupt practice by order of a competent court, consequent upon an election petition filed under and in accordance with the provisions of this Act or rules made thereunder.

- (b) holds a salaried whole-time or part-time appointment under a local authority, a University or any Corporation, Body, Enterprise or Co-operative Society, which is either controlled wholly or partly financed by the State Government;

- (c) has been dismissed from State Government service for misconduct involving moral turpitude and has been declared to be disqualified for employment in the public service;

- (d) holds any salaried post or place of profit under any Panchayati Raj Institution;

- (e) has directly or indirectly by himself or by his partner, employer or employees, any share or interest in any contract with, by or on behalf of the

Panchayati Raj Institution concerned while owning such share or interest in any work done for;

- (f) is a leper or is suffering from any other bodily or mental defect or disease rendering him incapable for work;
- (g) has been convicted of any offence by competent court and sentenced to imprisonment for six months or more, such sentence not having been subsequently reversed or remitted or the offender pardoned;
- (gg) is under trial in the competent court which has taken cognizance of the offence and framed the charges against him of any offence punishable with imprisonment for five years or more;
- (h) is for the time being ineligible for election under section 38;
- (i) has not paid, for two months from the date of the presentation of the notice of demand therefor, the amount of any tax or fees imposed by the Panchayati Raj Institution concerned;
- (j) is employed as a legal practitioner on behalf of or against the Panchayati Raj Institution concerned;
- (k) has been convicted of an offence punishable under the Rajasthan Prevention of Mrityu Bhoj Act, 1960;
- (l) has more than two children;
- (m) earlier having been a Chairperson / Deputy Chairperson of any Panchayati Raj Institution has not paid dues even after the expiry of a period of two months from the date a notice, for depositing the dues of the Panchayati Raj Institution, was duly served upon such Chairperson / Deputy Chairperson and his name is included in the list of such defaulter supplied by the State Government to the Collector (Panchayats) at least two months before the issue of

notification for election to such Panchayati Raj Institution;

- (n) in the case of a seat reserved for the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Backward Classes of the State, is not a member of any of those Castes, or Tribes or Classes, as the case may be;
- (o) in the case of a seat reserved for the women, is not a woman; and
- (p) in the case of a seat reserved for women belonging to Scheduled Castes or Schedules Tribes or Backward Classes, is not a member of any of these Castes or Tribes or Classes, as the case may be, and is not a woman;

Provided that -

- (i) a person shall not, by reason only of his being a share-holder in or a member of any incorporated company or cooperative society registered under the law for the time being in force in the State of Rajasthan, be held to be interested in any contract entered between the company or cooperative society and the Panchayati Raj Institution;
- (ia) for the purpose of clause (aa), a person shall be deemed to be disqualified for a period of six years from the date of order referred to in clause (aa);
- (ii) for the purposes of clauses (c), (g) and (k), any person shall become eligible for election after a lapse of six years from the date of his dismissal or the date of conviction, as the case may be;
- (iii) for the purpose of clause (i), a person shall not be deemed to be disqualified if he has paid the amount of the tax or fee due from him before the date of filling his nomination papers;
- (iv) the birth during the period from the date of commencement of this Act, hereinafter in this

proviso referred to as the date of such commencement, to 27th November, 1995, of an additional child shall not be taken into consideration for the purpose of the disqualification mentioned in clause (1) and a person having more than two children (excluding the child, if any, born during the period from the date of such commencement to 27th November, 1995) shall not be disqualified under that clause for so long as the number of children he had on the date of commencement of this Act does not increase;

- (v) for the purposes of clause (m), a Chairperson / Deputy Chairperson shall not be deemed to be disqualified if he pays the amount due from him before filing his nomination papers.

Explanation.- For the purpose of clause (l) of Section 19, where the couple has only one child from the earlier delivery or deliveries on the date of commencement of this Act and thereafter, any number of children born out of a single subsequent delivery shall be deemed to be one entity.

XX

XX

XX

XX

XX

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

पृथ्वी राज,
विशिष्ट सचिव।

(सुरेन्द्र गोयल, प्रभारी मंत्री)

**THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT)
BILL, 2015**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

PRITHVI RAJ,
Special Secretary.

(Surendra Goyal, **Minister-Incharge**)